प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक

संस्थापक स्व. श्री ठाकुरदासजी खुजनेरी

मालव समाचार

इंदौर | ■ वर्ष : 61 ■ अंक 07 ■ 15 फरवरी 2025 ■ पृष्ठ-12 ■ मूल्य - 3.00

प्रकाशन के 6 दशक

27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी रिटर्न

दिल्ली के दिल मे मोदी

पहली बार डबल इंजन सरकार, ढह गई आप की इमारत

कल्पना नही की होगी 'मफ़लर मेन' ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया गया नया नामकरण 'आपदा' इतना कारगर साबित हो जाएगा। न ये उम्मीद थी कि दिल्लीवासी इस नाम को दिल पर ले लेंगे। परिणाम ये रहा कि दिल्ली से 'आपदा' चली गई और भाजपा आ गई।

बीजेपी ने दो साल पहले बनाया

दिल्ली विजय का प्लान

विशेष रिपोर्ट पेज-6-7-8

एक ज़मीन से जुड़े लोगों का मंत्री

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय दिल्ली से इंदौर की मेरी यात्रा के दौरान, मैंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा जिसने मुझे रोमांचित कर दिया। मैंने श्री कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, को देखा, जो किसी अन्य यात्री की तरह लाइन में खड़े थे, इकोनॉमी क्लास में चढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे।

भले ही बिजनेस क्लास लगभग खाली था, उन्होंने इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने का विकल्प चुना, चुपचाप अपनी सीट ली और एक छोटी सी पुस्तक पढ़ने में डूब गए। अपने 30 सालों की यात्रा में –चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय –मैंने कभी भी किसी वरिष्ठ राजनेता, राष्ट्रीय खेल हस्ती, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, या अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों को इकोनॉमी क्लास चुनते हुए नहीं देखा।

ऐसे विनम्र और सिद्धांतों पर चलने वाले नेता को सलाम, जो उदाहरण द्वारा नेतृत्व करते हैं, सरलता और सरकारी धन के जिम्मेदार उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। उनके कार्य ईमानदारी और सच्ची सार्वजनिक सेवा की भावना को दर्शाते हैं। यह अन्य मंत्रियों और सेलिब्रिटीज़ के लिए एक सबक है, जो अक्सर जनता के खर्च पर लक्जरी का आनंद लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता प्रशासन में विनम्रता और जवाबदेही के लिए एक नया मानक स्थापित करते हैं।

■ डॉक्टर राजेश खुजनेरी

संगठन से चूके तो अब सत्ता पर नजर...

निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों में लग सकती है कई नेताओं की लॉटरी

पेज- 03

पीएम मोदी के तीर्थ दर्शनों में छिपा है कमल खिलाने का राज!

संगम स्नान से निकला राजनीतिक संदेश....
क्या बिखरे हिंदू वोटों को एक कर पाएगी बीजेपी?

पेज- 11

नीतीश के *सियासी चक्रव्यूह* को तोड़ने में फेल हुए लालू

मुख्यमंत्री 'T' और 'R' टेंशन से दूर, तेजस्वी को तनाव

पेज- 9

जिलों के प्रभारी मंत्री पद को लेकर महायुति में मतभेद!

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें

पेज- 10

GYAN पर ध्यान... मिडिल क्लास पर भी मेहरबान

बजट की वो बातें... जो आम आदमी को कर रही *बमबम!*

पेज- 05

नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब,
किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता।

निवेशकों का बढ़ता विश्वास, क्षेत्रीय उद्योगों का संपूर्ण विकास

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

INVEST MADHYA PRADESH

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
फरवरी 2025, भोपाल

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को बढ़ाने के लिए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
की पहल पर क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है।
नये निवेश से क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों की उन्नति के साथ
युवाओं के लिए रोज़गार के नये अवसरों से नई राहें खुल रही हैं।

उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलूरु, कोलकाता में हुए निवेशकों के साथ इंटरेक्टिव सत्रों में कुल 2 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 3.28 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे

निवेशकों को विशेष सुविधाएं और नीतियां-

सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन योजना और कस्टमाइज पैकेज जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। नए निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है।

एक्सपोर्ट हब बनता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कनेक्टिविटी, उद्योग-अनुकूल नीतियां और मजबूत अधोसंरचना से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि : पिछले वित्त वर्ष में 13,158 करोड़ रुपए के दवा उत्पादों का निर्यात। निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य : आने वाले तीन वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का संकल्प, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।

Website : invest.mp.gov.in

D-19293/24

संगठन से चूके तो अब सत्ता पर नजर...

भोपाल (विनोद उपाध्याय)। मप्र में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट से वंचित नेताओं के साथ ही जिला अध्यक्ष बनने से चूके नेताओं की नजर अब निगम-मंडलों पर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए सरकार निगम-मंडलों में अध्यक्ष के पद पर उन्हें पदस्थ करेगी। इन नियुक्ति के समय नेताओं की वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जाएगा। वरिष्ठ नेताओं को जहां कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा, वहीं अन्य नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा भी मिलता है।

“आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे चलेंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी मौका मिल जाएगा। लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जो रसीद कट्टे दिए थे उनका क्या किया। सदस्यता काम का आधार भी बनेगी।”

-**डॉ. मोहन यादव**, सीएम (24 अगस्त को बीजेपी कार्यालय में दिया बयान)

मोहन सरकार कर चुकी है तीन राजनीतिक नियुक्तियां

विजयपुर के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल, कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर विजयपुर में उपचुनाव हुए। पार्टी ने रावत को पहले ही मंत्री बना दिया है। वे चुनाव मैदान में थे चूंकि विजयपुर में आदिवासी वोटर्स ज्यादा हैं इसलिए सीताराम को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह मोहन नागर को जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष और श्रीकांत पाटिल को क्रिप्स का एमडी बनाया गया है।

सक्रिय नेता होंगे एडजस्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों इस बात के संकेत दिए थे, कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बाद निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। इसके पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने संगठन पर्व में अच्छा काम करने वालों को भविष्य में एडजस्ट करने की बात कही थी। गौरतलब है कि पार्टी ने इस बार जिलाध्यक्ष के लिए साठ साल की उम्र का क्राइटेरिया तय किया था। अपवाद छोड़ दें तो हर जगह इसका पालन किया गया। ऐसे में सीनियर नेता अब खुद के लिए निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण में जगह मांग रहे हैं। प्रदेश संगठन के नेताओं से मिलकर कुछ नेताओं ने बाकायदा अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है।

निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों में लग सकती है कई नेताओं की लॉटरी

गौरतलब है कि प्रदेश में 40 से अधिक निगम और मंडल हैं, जिनमें अध्यक्ष और कुछ निगम-मंडलों में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी नियुक्त होते हैं। अब भाजपा के नेताओं को बेसब्री से निगम और मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार बना हुआ है। जिलाध्यक्ष बनने से वंचित रहे कई नेताओं को निगम-मंडलों में जगह मिलने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद प्रदेश में भाजपा के संगठन के चुनाव के आखिरी दौर में अब अध्यक्ष का चुनाव होना ही बाकी रह गया है। यह चुनाव जैसे ही होगा ,तब नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की राय और उनकी सहमति के आधार पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के नेताओं का चयन होगा, जिन्हें निगम और मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर नियुक्त किया जाना है। इसी तरह ऐसे नेता जो कि निगम मंडलों में जगह नहीं पा पाएंगे इन नेताओं को भाजपा के प्रदेश संगठन में भी पदाधिकारी बनाया जाएगा।

प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को उखाड़ने के पश्चात ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से भाजपा की सरकार बनी और अभी हुए विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार भारी बहुमत के साथ बन चुकी है। इस दौर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे कांग्रेसी नेताओं को भी सत्ता और संगठन में जगह देना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे कुछ पूर्व कांग्रेसियों को भी भाजपा निगम और मंडलों में जगह दे सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय दूसरे दल से भाजपा में शामिल हुए नेता जो भाजपा संगठनात्मक चुनाव में पार्टी के क्राइटेरिया की वजह से जिलाध्यक्ष की दावेदारी नहीं कर सके, वह भी निगम-मंडल में अपनी दावेदारी कर रहें है। इसके लिए वह अपने क्षेत्र में पिछले चुनाव में किए गए अपने काम को आधार बना रहे हैं। हालांकि संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हीं आयोग, बोर्ड में नियुक्तियों पर विचार हो रहा है, जिनमें नियुक्तियां बेहद जरूरी हैं।

सबको साधने की चुनौती

भाजपा की संगठनात्मक नियुक्ति के बाद खाली हाथ रह गए कई नेताओं की नजर अब निगम-मंडलों पर टिक गई है। विकास प्राधिकरणों, मप्र पर्यटन विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड से लेकर अन्य निगम-मंडल और बोर्डों में नियुक्ति होना है। ऐसे में नेताओं को अब निगम-मंडल से ही आस बाकी है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय निगम-मंडलों के पद खाली हैं। नगर निगम चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव फिर संगठनात्मक नियुक्तियों से पार्टी के जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है उन सबको साधने की चुनौती होगी। पार्टी में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो 50-55 की उम्र पार कर चुके हैं। पार्टी के लिए दशकों से समर्पित भाव से काम कर रहे इन नेताओं को इंतजार था कि संगठन कोई जिम्मेदारी सौंपेगा। नगर निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों से पहले उनके नाम सुर्खियों में आ जाते हैं। इन नेताओं से लेकर उनके परिजनों और समर्थकों को आस जग जाती है लेकिन हर बार खाली हाथ रह जाते हैं।

राजनीतिक नियुक्ति के लिए शुरू हुई प्रक्रिया

भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में जिलाध्यक्ष की दौड़ में पीछे रहने वाले कई नेता अब निगम-मंडलों, आयोग और विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति को लेकर नियुक्ति अपने-अपने आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश निगम मंडल और प्राधिकरण अभी खाली पड़े हैं। मप्र भाजपा ने अपने सभी 62 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया बाकी रह गई है। ऐसे में जिन नेताओं ने जिलाध्यक्ष के पद को लेकर दावेदारी पेश की थी और किसी वजह से वह इसमें पीछे रह गए वह अब निगम-मंडल में नियुक्ति के लिए दावेदारी कर रहे है। ऐसे नेताओं में ग्वालियर, चंबल, मालवा और विंध्य क्षेत्र के नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद के लिए पूरा जोर लगाया था लेकिन वरिष्ठ नेताओं की अपने चहेतों को इस पद पर बैठाने की जिद ने इनकी दावेदारी को बौना साबित कर दिया। इसके बाद अब यह नेता आगामी माह में निगम-मंडलों में होने वाली नियुक्ति के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

क्राइटेरिया में नेताओं की लिस्ट लंबी...

मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही निगम-मंडल के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। ये राजनीतिक नियुक्तियां होंगी इसलिए नेता अपने-अपने तरीके से पद हासिल करने की जुगाड़ में हैं। हालांकि, सरकार और संगठन ने इसके लिए क्राइटेरिया तय किए हैं। इनमें डॉ. हितेश बाजपेयी, नरेंद्र बिरथरे, गौरव रणदिवे, यशपाल सिंह सिसोदिया, विनोद गोटिया , लोकेंद्र पाराशर, शैलेंद्र बरुआ , जितेंद्र लिटोरिया सुरेश पचौरी ,पूर्व सांसद गजेंद्र राजूखेड़ी, शिवदयाल बागरी, दिनेश अहिरवार और शशांक भार्गव, दीपक सक्सेना, पन्ना के संजय नगाइच और जबलपुर के धीरज पटैरिया,गुना से सांसद रहे केपी यादव ,जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। इन क्राइटेरिया के अलावा ऐसे नेताओं को भी निगम-मंडल या प्राधिकरण में उपकृत किया जा सकता है, जिन्होंने सदस्यता अभियान में बेहतर प्रदर्शन किया।

12 महीने पहले निरस्त हुई थीं नियुक्तियां

डॉ. मोहन यादव सरकार ने 13 फरवरी को आदेश जारी कर 46 निगम, मंडल और प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। इन सभी की नियुक्ति शिवराज सरकार के समय हुई थी। निगम-मंडल और प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त था ।डॉ. मोहन सरकार द्वारा हटाए गए कई अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का कार्यकाल तीन साल से ज्यादा का था। सीएम ने विधानसभा सत्र चलने के दौरान इन सभी को एक ही आदेश में हटाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि वे नया सेटअप चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए पार्टी नेतृत्व से फ्री हैंड मिला है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने निगम-मंडलों में नियुक्तियां पहले ही कर दी थी।

महाकुंभ की त्रासदी

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर तड़के हुए हादसे में कुछ श्रद्धालुओं की मौत की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। यूं तो अतीत में भी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक व उज्जैन के कुंभों के दौरान भी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हम अतीत के हादसों से कोई सबक ले पाए हैं? यूं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मेला प्रबंधन व सुरक्षा के चाकचौबंद बंदोबस्त के दावे किए गए थे, लेकिन मौनी अमावस्या की घटना ने यह दुखद स्थिति पैदा कर दी है। करोड़ों तीर्थयात्रियों का अचानक किसी धार्मिक आयोजन में पहुंचना निश्चित रूप से शासन व प्रशासन के लिये बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद शासन-प्रशासन की प्राथमिकता दुर्घटना मुक्त आयोजन ही होना चाहिए। दरअसल, ऐसे आयोजनों में तीर्थयात्रियों की जल्दीबाजी और पहले स्नान करने की होड़ अकसर ऐसी भगदड़ पैदा कर देती है। जो बताती है कि हम सार्वजनिक जीवन में ऐसे बड़े आयोजनों में अनुशासित व्यवहार करने से चूक जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम इस बात का भी संकेत है कि कुंभ के आयोजनों में पिछले बड़े हादसों के सबक हम पूरी तरह सीख नहीं पाए हैं। हालांकि, शासन-प्रशासन को इस बात का अंदाज था कि इस बार करोड़ों की भीड़ जुटेगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सावधानी में चूक तो हुई है। निस्संदेह, महाकुंभ का आयोजन भारतीय सनातन परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है। बिना चिट्ठी व तार देश के कोने-कोने से तीर्थयात्री महाकुंभ में जुटते हैं। कल्पवास में संयमित जीवन से आध्यात्मिक लाभ अर्जित करते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ यातायात के साधनों की उपलब्धता से ऐसे आयोजनों पर भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया की सक्रियता ऐसे आयोजन के प्रति अतिरेक आकर्षण पैदा कर देती है, जिससे श्रद्धालुओं का अप्रत्याशित सैलाब कुंभ नगरी की तरफ मुड़ जाता है। निश्चित रूप से समय के साथ आये सामाजिक बदलावों के मद्देनजर शासन-प्रशासन को महाकुंभ के आयोजन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

निश्चित रूप से महाकुंभ के आयोजन से जुड़े तंत्र को उन कारकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिसके चलते इस त्रासदी की छाया प्रयागराज महाकुंभ पर पड़ी। उन तमाम संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो कुंभ जैसे बड़े आयोजनों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने में सहायक हो सकती हैं। हालांकि, प्रयागराज महाकुंभ में एआई, ड्रोन व कंप्यूटरों के जरिये व्यापक सुक्षा प्रबंधों की निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी भी अफवाहों व भगदड़ की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। तीर्थयात्रियों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि वे धैर्य के साथ अपनी स्नान की बारी का इंतजार करें। साथ ही अफवाहों व जल्दीबाजी से बचें। बताया जाता है कि प्रयागराज हादसे में भी कुछ तीर्थयात्रियों द्वारा स्नान में जल्दीबाजी करने तथा अखाड़ा मार्ग पर लगे बैरिकेड्स पर चढ़ने पर मची अफरातफरी को कारण बताया गया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस व अधिकारियों की चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से वे भीड़ के मिजाज को समय रहते भांप लिया जाता तो शायद हादसे को टाला जा सकता। हालांकि, मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। साथ ही न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद इस बात की गहन जांच जरूरी है कि स्थिति कैसे नियंत्रण से बाहर हो गई। यह एक निर्विवाद सत्य है कि गोपनीयता का पर्दा डालने से केवल अफवाहों व गलत सूचनाओं को ही बढ़ावा मिलता है। बहरहाल, आने वाले समय में श्रद्धालुओं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने की भी जरूरत होगी कि वे अपने आसपास के घाट पर ही स्नान करके समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह भी कि संगम के सभी घाट समान रूप से पवित्र हैं। इससे चुनिंदा घाटों पर तीर्थयात्रियों का दबाव नहीं बनेगा। साथ ही श्रद्धालुओं को अनुशासित व्यवहार के लिये प्रेरित किया जाना भी बेहद जरूरी है। ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

महाकुंभ में संघ के स्वयंसेवकों के समर्पण और सेवा भाव से अभिभूत हुए श्रद्धालु

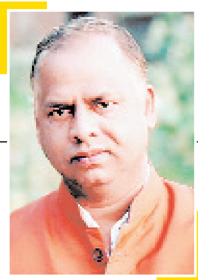

कृष्णमोहन झा

"प्रयाग राज में गत माह प्रारंभ हुए महाकुंभ को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार को समाज के हर वर्ग का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनेक समाजसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों के लाखों कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रतिदिन पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के कुशल प्रबंधन और संगम में उनके लिए सुविधाजनक स्नान सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह चौबीसों घंटे समर्पित भाव से जुटे हुए हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इसी सराहना के हकदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे हजारों स्वयंसेवक भी हैं जिन्हें संघ द्वारा प्रयागराज में संपूर्ण समर्पण एवं निष्ठा के साथ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए महाकुंभ मेला स्थल पर तैनात किया गया है।"

संघ के सेवाभावी स्वयंसेवक प्रतिदिन देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के महाकुंभ प्रवास को सुगम बनाने में पूरी तन्मयता के साथ प्रशासन का जिस तरह सहयोग कर रहे हैं। उससे श्रद्धालुओं का अभिभूत होना स्वाभाविक है लेकिन संघ के सेवाभावी स्वयंसेवकों के प्रति वे जब ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं तो संघ के स्वयंसेवक विनम्रता पूर्वक बस यही कहते हैं कि महाकुंभ में भी वे सेवा की उस महान परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं जिसके लिए संघ को जाना जाता है।

संघ के हजारों स्वयंसेवक महाकुंभ के शुभारंभ के कुछ दिन पूर्व से ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी प्रवेश द्वारों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए नित्य प्रति प्रयागराज पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं का पहले वे विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन करते हुए उनकी कुशल क्षेम पूछ कर उन्हें स्वल्पाहार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और फिर सुगमतापूर्वक घाट तक पहुंचने के लिए सही मार्ग बताते हैं। डुबकी लगाने के बाद जब ये श्रद्धालु वापस लौटते हैं तो संघ के स्वयंसेवक उनके लिए न केवल निशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा नगर के अन्य निर्गम द्वारों तक पहुंचाने का इंतजाम भी करते हैं। प्रयागराज में हजारों की संख्या में मौजूद संघ के स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा की जो मिसाल पेश कर रहे हैं उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है।

संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बुजुर्ग श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संघ के कार्यकर्ता उन्हें घाट तक पहुंचने के लिए स्कूटी सेवा कराई गई है। जिन बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पैदल चलने में कठिनाई महसूस होती है उन्हें संघ के कार्यकर्ता स्कूटी पर बिठा कर न केवल घाट तक पहुंचाते हैं अपितु स्नान के पश्चात् उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर स्कूटी पर बिठा कर स्टेशन अथवा बस स्टैंड तक भी छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, संघ के कार्यकर्ता कुंभ मेला की अपार भीड़ में अपने परिजनों से बिछुड़ गये श्रद्धालुओं को पुन: उनके परिजनों से मिलाने के काम में भी जुटे हुए हैं। इसके लिए संघ के स्वयंसेवकों ने एक व्हाट्स एप ग्रुप बना लिया है जिससे देश भर के स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं। जब भी महाकुंभ के जनसैलाब में उन्हें किसी व्यक्ति के अपने परिजनों से बिछुड़ जाने की जानकारी मिलती है वे उस व्यक्ति की फोटो सहित संपूर्ण पते की जानकारी व्हाट्स एप ग्रुप में साझा कर देते हैं। फिर संबंधित जिले और शहर के स्वयं सेवक उस जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति के परिजनों को खोज निकालते हैं इस तरह हजारों बिछुडे हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलवाने में संघ के स्वयंसेवकों की अहम भूमिका रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने महाकुंभ मेला परिसर को पालीथीन और कचरा मुक्त बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है।इसी पुनीत उद्देश्य से संघ के द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए गंगा सेवा दूत महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पालीथीन का उपयोग न करने के प्रेरित कर रहे हैं। ये स्वयंसेवक किसी श्रद्धालु के हाथ में पालीथीन का बैग दिखाई पड़ते ही उससे वह पालीथीन लेकर उसे कपड़े का थैला और थाली भेंट करते हैं। महाकुंभ मेला परिसर को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए संघ की इस पहल की सर्वत्र सराहना हो रही है। गौरतलब है कि संघ ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच वितरित करने के लिए देश भर से थैला और थाली संग्रह अभियान चलाया था जिसमें लोगों ने दिल खोलकर योगदान किया। महाकुंभ में संघ के स्वयंसेवक जिस तरह समर्पण और तन्मयतापूर्वक श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा में जुटे हुए हैं उसकी चर्चा केवल प्रयागराज और उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी हो रही है। महाकुंभ परिसर में श्रद्धालुओं की हर संभव मदद के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहने वाले स्वयंसेवकों ने सेवा, समर्पण और संस्कार की जो मिसाल पेश की है वह अन्य श्रद्धालुओं को इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रेरित कर रही है।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

GYAN पर ध्यान... मिडिल क्लास पर भी मेहरबान

बजट की वो बातें... जो आम आदमी को कर रही बमबम!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सियासी अखाड़े का माहिर पहलवान यूं ही नहीं माना जाता। सियासी समीकरण साधने की अपनी कला के दम पर ही वे पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए थे। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में भी सियासी समीकरण साधने का बड़ा प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता जनार्दन का बजट बताया है। बजट 2025-26 का फोकस GYAN पर है। यह GYAN भारत के उन लोगों का समूह है जो बीजेपी के बड़े वोटर में शामिल हैं। GYAN मतलब G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी किसान और N-नारी। मोदी सरकार ने इस बजट में इन चार कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार नौकरीपेशा लोगों को भी बमबम कर दिया है। मध्य वर्ग की हमेशा शिकायत कमाई पर करों में छूट से रहती थी। इस बजट में सरकार ने नौकरी कर रहे लोगों को एकमुश्त बंपर राहत दी है।

चुनावी राज्यों पर मेहरबानी... क्या है मोदी सरकार के बजट का सियासी संदेश?

कई यूनियनों ने किया बजट का दिल खोलकर स्वागत

कुल मिलाकर मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में कई ऐसी खूबियां दिख रही हैं जिसकी विभिन्न संगठनों की ओर से काफी तारीफ की जा रही है। दिल्ली के विभिन्न बाजारों की यूनियनों ने सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का दिल खोलकर स्वागत किया है। एक यूनियन के पदाधिकारी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन कदमों का ऐलान किया होता तो एनडीए को 400 से कम सीटें नहीं मिलतीं। मोदी सरकार की ओर से की गई बजट घोषणाओं पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया से साफ है कि उन्हें इस बजट में कमी निकालने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। यही कारण है कि वे बजट में कमियां निकालने की जगह सियासी बयानबाजी में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह बजट बड़ा असर डालने वाला साबित हो सकता है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब,युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये 10 क्षेत्रों में फैले हैं ।बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। मिडिल क्लास को खुश करके दिल्ली चुनाव का समीकरण साधने की कोशिश की गई है तो बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य पर सौगातों की बरसात की गई है। अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर असम का भी ख्याल रखा गया है।

बजट में GYAN का समीकरण साधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि यह बजट ज्ञान (GYAN) का होगा। GYAN का मतलब बिल्कुल साफ है। G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता यानी कि किसान और N-नारी । मोदी सरकार के इस बजट में इन चार वर्गों के लिए खजाना खोल दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब,युवा, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये उपाय 10 क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके जरिए इन वर्गों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। देश की 70 फीसदी आबादी किसानों की है जिन पर मोदी सरकार ने खास मेहरबानी दिखाई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़कर पांच लाख कर दी गई है। इस तरह किसान पांच लाख तक का लोन बिना ब्याज के ले सकेंगे। किसानों के लिए पीएम धन-धान्य योजना का ऐलान किया गया है। यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है।

नागरिकों की जेब भरने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता जनार्दन का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट भारत की मजबूत नींव रखने वाला है और इससे हर भारतीय के सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बजट से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे ।उन्होंने बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। यह देश के नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है और इससे आत्मनिर्भर भारत को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में आमतौर पर फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा मगर इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी। इस बजट में देश के मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया है।

इन घोषणाओं का आम लोगों पर होगा बड़ा असर

मोदी सरकार की ओर से मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक कार जैसे सामानों को सस्ता करने की घोषणा को भी आम लोगों पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। कैंसर के रोगियों को सुविधाएं देने के साथ ही 36 जरूरी दवाओं को शुल्क में छूट देने का ऐलान भी आम जनता के लिए काफी मददगार साबित होगा। कई सामानों से सेस खत्म करने की घोषणा से भी लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

दलित और आदिवासी महिलाओं का ख्याल

संविधान और आरक्षण का मुद्दा गरमाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए भाजपा इस दिशा में काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। दलितों और आदिवासियों को साधने के लिए मोदी सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाया है। दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है ।एससी और एसटी समुदाय की पांच लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों वर्गों की फर्स्ट-टाइम आंत्रप्रेन्योर महिलाओं को अगले 5 वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की तैयारी है।

देश के युवा वर्ग को साधने की कवायद

सरकार ने बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों के दौरान मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। आईआईटी में भी सीट बढ़ाने की तैयारी है जिससे युवाओं को फायदा होगा ।चुनावी राज्य बिहार में पटना आईआईटी का विस्तार करने की घोषणा भी की गई है। एजुकेशन और कौशल विकास पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा जिसे युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

मिडिल क्लास के लिए कर दिया बड़ा ऐलान

देश के मिडिल क्लास को साधन के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने में इस वर्ग की बड़ी भूमिका रही है और चुनावी राज्यों में भी जीत-हार तय करने में यह वर्ग बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसे में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को खुश करने के लिए 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय बात यह है कि चुनावी राज्य दिल्ली में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख तक करने का अनुरोध किया था मगर मोदी सरकार ने उनकी डिमांड से दो लाख अधिक तक की आय को आयकर से छूट देने की घोषणा कर दी है इसके साथ ही 75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का बड़ा असर दिख सकता है और आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है।

बिहार से असम तक को साधा

वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ हो गया है कि बिहार को सबसे अधिक तवज्जो दी गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए बिहार की झोली सौगातों से भर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किए जाने की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की बात भी कही गई है। पटना आईआईटी का विस्तार करने और पटना हवाई अड्डे की क्षमता में विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी मोदी सरकार की ओर से बिहार को कई सौगातें दी गई हैं ।बिहार में तीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति विशेष रूप से आभार जताया है ।बिहार के बाद असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और असम के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले यूरिया प्लांट को लगाने की घोषणा की गई है ।सरकार के इस कदम से असम में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे और इसे असम का सियासी समीकरण साधने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है। असम में एनडीए की मजबूत पकड़ रही है और मोदी सरकार ने इसे पकड़ को आगे भी बनाए रखना के लिए बड़ा सियासी दांव चला है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार

27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी रिटर्न

दिल्ली के दिल मे मोदी ,पहली बार डबल इंजन सरकार, ढह गई आप की इमारत

नई दिल्ली। कल्पना नही की होगी 'मफ़लर मेन' ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया गया नया नामकरण 'आपदा' इतना कारगर साबित हो जाएगा। न ये उम्मीद थी कि दिल्लीवासी इस नाम को दिल पर ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के इसी नए नामकरण के साथ दिल्ली चुनाव में इंट्री की थी। उनकी पहली ही सभा में, उन्होंने 'आप' को दिल्ली के लिए 'आपदा' करार दिया था। तब ये शब्द महज़ जुमला नज़र आया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आप..वाकई आपदा में तब्दील होती गई। जनसामान्य की जुबां तक ये शब्द पहुँच गया। परिणाम ये रहा कि दिल्ली से 'आपदा' चली गई और भाजपा आ गई।

दिल्ली की ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और पार्टी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की मेहनत का प्रतिफ़ल हैं। तीनों नेताओं की जुगलबंदी से आप की झाड़ू के तिनके बिखेर दिए और स्वयम की पार्टी का 27 साल का सत्ता का सूखा दूर कर दिया। अब कमलदल 'इंद्रप्रस्थ' के सिंहासन' पर विराजमान हैं और वो भी पूरे रुतबे के साथ। भाजपा 8 से 48 हो गई और आप 62 से 22 पर आ गई। कांग्रेस का तो कोई' पुरसाने-हाल' ही नही रहा। वह लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में अपना खाता नही खोल पाई। कांग्रेस ने दिल्ली में शून्य की डबल हैट्रिक मार ली। पार्टी के लिए इससे शर्मनाक और क्या होगा कि उनके दल के 70 उम्मीदवारों में से 67 अपनी जमानत भी नही बचा पाए। यानी सबकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। फ़िर भी कांग्रेस खुश हैं कि उसने आम आदमी पार्टी से हरियाणा हार का बदला ले लिया।

सत्ता विरोधी लहर में मजबूत पिलर धड़ाम हो गए

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकली आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बीते पांच सालों में पड़े भ्रष्टाचार के छीटों को झाड़ू साफ नहीं कर सकी। दिल्ली में पार्टी का तिनका-तिनका बिखर गया। शासन के दिल्ली मॉडल के सहारे पूरे देश में पैठ बनाने की कोशिश कर रही आप को दिल्लीवालों ने नकार दिया। बड़े सवालिया निशान आप की शासन व्यवस्था पर भी लगे। केंद्र सरकार से बार-बार झगड़ने वाली आप सरकार पर यकीन जताने की जगह दिल्लीवासियों ने डबल इंजन की सरकार को चुना। सत्ता विरोधी लहर इतनी तेज रही कि आलाकमान अरविंद केजरीवाल, पार्टी में नंबर-2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत दूसरे मजबूत पिलर धड़ाम हो गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री आतिशी भी हारते-हारते चुनाव जीत सकीं।

2020 से डगमगाने लगा था आप का नैतिक आधार

दिल्ली में 2020 में मिले मजबूत जनादेश के साथ ही आप को नैतिक आधार भी डगमगाने लगा था। इसकी शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से हुई थी। 30 मई 2022 को ईडी ने मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। यह आप पर लगा पहला बड़ा झटका था। इससे पहले आप के जिन नेताओं पर आरोप लगे, उनसे पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन जेल जाने के बाद लंबे समय तक जैन बिना जिम्मेदारी के मंत्री बने रहे। यहां तक कि इस चुनाव में भी आप ने जैन को मैदान में उतारा था।

शराब घोटाले ने कराया सबसे अधिक नुकसान

जानकारों की मानें तो आप को सबसे ज्यादा नुकसान कथित शराब घोटाले से हुआ। इसमें मंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत मुख्यमंत्री केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा। पार्टी बेशक खुद के आरोपों को सियासी साजिश करार दे रही है, लेकिन आरोपों ने पार्टी की उस बुनियाद को ही चूर-चूर कर दिया, जिस पर पूरी इमारत खड़ी की गई थी। आप नेताओं पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और सभी नेता जमानत पर हैं। फिर भी, जनता की अदालत ने इन्हें नकार दिया है।

आप नेतृत्व की साख पर बट्टा

चुनावी अभियान के दौरान आप नेतृत्व के नेता विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाते दिखे। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग जैसी सांविधानिक संस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली पुलिस को भाजपा की पुलिस तक करार दे दिया। यहां तक कि हरियाणा व केंद्र सरकार पर साजिशन यमुना में जहर मिलाने और जनसंहार करने तक के आरोप मढ़ दिए। आम लोगों में इसका असर नकारात्मक पड़ा। बातचीत में कई मतदाताओं ने इसे आप का बचकाना आरोप करार दिया। इससे लोगों में आप की बची-खुची साख पर बट्टा लग गया।

आप का शासन मॉडल चकनाचूर

यमुना की सफाई, टूटी सड़कें, पेयजल संकट, सीवर की समस्या समेत अपनी दूसरी नाकामियों के लिए आप नेतृत्व लगातार भाजपा को जिम्मेदार बताता रहा। अपने पूरे चुनावी अभियान में पार्टी ने केंद्र सरकार पर काम न करने देने की बात कही, लेकिन कोई नेता इसका ठोस जवाब नहीं दे सका कि वह दोबारा सरकार बनाने पर उसी केंद्र सरकार के साथ कैसे काम कर सकेंगे। इससे आम लोगों ने आप के आरोपों के साथ जाने को तवज्जो नहीं दी। इसकी जगह दिल्ली के शासन मॉडल की नाकामी का जवाब भाजपा में यकीन जताकर ढूढ़ा।

दिल्ली के दंगल में कांग्रेस न दिखा पाई दम, 67 की जमानत जब्त

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से सिर्फ तीन सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी। इतना ही नहीं, यह लगातार ऐसा तीसरा चुनाव साबित हुआ, जहां कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कांग्रेस के साथ कुल 554 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। बीएसपी के सभी 69 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। वहीं, एआईएमआईएम के भी 12 में से 10 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए ।देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। उसने करीब 6.4 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26 प्रतिशत वोट मिले थे। एआईएमआईएम के 12 में से दो उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचा ली है। ओखला सीट से शिफा उर रहमान दूसरे स्थान पर रहे जबकि मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन ने 16.6 प्रतिशत वोट पाकर अपनी जमानत बचा ली है। कांग्रेस के जो तीन उम्मीदवार दिल्ली में अपनी जमानत बचाने में सफल रहे उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल हैं जिन्हें 40 हजार से अधिक मत और 27 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले। वह तीसरे स्थान पर रहे ।दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त न सिर्फ अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, बल्कि दूसरे स्थान पर भी रहे। यह दिल्ली की इकलौती सीट हैं जहां कांग्रेस दूसरे पर स्थान पर रही ।संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, मुदित अग्रवाल, हारुन यूसुफ और राजेश लिलोठिया ऐसे नेता रहे जो अपनी जमानत बचाने में विफल रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर से 6384 वोट, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को 16549 वोट तथा दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर फरहाद सूरी को जंगपुरा से 7350 वोट हासिल हुए। दिल्ली की राजनीति में 1998 से 2013 तक अपना सुनहरा दौर देखने वाली कांग्रेस के लिए यह लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव था जिसमें उसे एक भी सीट नहीं मिली।

दिग्गजों की भरमार, किसके सिर सजेगा ताज

अब सबका ध्यान इस बात पर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चूंकि पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां हैं जो इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, ऐसे में आलाकमान की माथापच्ची बढ़ गयी है। साहिब सिंह वर्मा भाजपा के आखिरी प्रमुख चेहरे थे, जो 1996 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद सुषमा 52 दिनों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में भाजपा जीत नहीं पाई। सुषमा के अलावा भाजपा ने डॉ. हर्षवर्धन, किरण बेदी और मनोज तिवारी जैसे कई बड़े नामों के साथ प्रयोग किया, लेकिन सफल नहीं रही। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी (आप) की लहर को कोई पार्टी नहीं रोक पाई। अब जब भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी है तो कई वादों को पूरा करने की चुनौती के साथ उसके सामने सीएम चेहरा चुनना बड़ी चुनौती है। वैसे प्रवेश वर्मा अभी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया है। एक अन्य दावेदार रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुप्ता संगठनात्मक कौशल और सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को भी दावेदार माना जा रहा है। सिरसा एक प्रमुख सिख नेता और लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इसका असर पंजाब में भी बढ़ सकता है। संभावित नामों में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख सतीश उपाध्याय भी हैं। उन्होंने सोमनाथ भारती को हराया है। इसके अलावा कोई चौकाने वाला नाम भी आ सकता है।

संगठन पर संकट, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से विधायक तक हुए दूर

कई तरह के आरोपों से घिरी आप सांगठनिक स्तर पर कमजोर होती गई। आम कार्यकर्ताओं की छोड़िए, विधायकों तक की बात सुनने वाला कोई नहीं था। यही वजह रही कि चुनाव से ऐन पहले एक साथ आठ विधायक भाजपा के साथ चले गए, जिनका टिकट आप ने काट लिया था। वहीं, जिन बाहरी लोगों को टिकट दिया, वह स्थानीय स्तर पर आप कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं बना सके। इसका नतीजा यह रहा कि वोटिंग के दिन कई पोलिंग बूथ ऐसे दिखे, जहां आप के काउंटर पर कार्यकर्ता ही नहीं थे। इसके उलट भाजपा के काउंटर पर भीड़ दिखी। भाजपा के लिए फ्लोटिंग वोटर्स का मन बदलने में यह रणनीति कारगर साबित हुई।

शीश महल विवाद से बढ़ी आम मतदाताओं की दूरी

केजरीवाल के आवास से जुड़े विवाद का असर भी मतदाताओं में नकारात्मक ही गया। भाजपा ने इसे शीश महल करार दिया था। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल के आवास की जो तस्वीरें बाहर आई, उसने दस साल में केजरीवाल की बनी बनाई इमेज को नुकसान पहुंचाया। इससे गरीब तबके में पैठ बनाने में भाजपा को सहूलियत हुई और आरक्षित श्रेणी की चार सीटें जीतने में भी कामयाबी मिली।

बीजेपी ने दो साल पहले बनाया दिल्ली विजय का प्लान

केजरीवाल से नाराज जाट-गुर्जरों को साधा, आरएसएस ने दिलाए झुग्गियों के वोट

विस्तृत खबर पेज-8 पर

आधी आबादी पर खूब चला भाजपा का जादू...

दिल्ली चुनाव में महिलाओं पर भाजपा का ऐसा जादू चला कि जिन 41 सीटों पर आधी आबादी ने ज्यादा मतदान किया, उनमें से 30 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। आप का फ्री बस का पैंतरा महिलाओं को लुभा नहीं पाया। पेयजल संकट, गंदा पानी व सीवर की समस्या को लेकर महिलाओं ने आप का साथ नहीं दिया। दअरसल, राजधानी में कुल 60.90 फीसदी महिलाओं तो 60.20 फीसदी पुरुषों ने मतदान किया था। 70 सीटों में से 41 पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। वर्ष 2020 के चुनाव में महिलाएं पुरुषों से मतदान करने में मात्र .09 फीसदी ही पीछे रही थीं, जबकि 31 सीटों पर पुरुषों से आगे थीं। आप, भाजपा व कांग्रेस ने कुल 26 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। भाजपा ने आठ को टिकट दिया जिनमें से शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम व ग्रेटर कैलाश से शिखा राय ने जीत का ताज पहना। वहीं, आप ने 9 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। केवल कालकाजी से आतिशी ही सीट बचा पाईं, जबकि कांग्रेस ने भी 9 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया था, जो हार गईं।

बीजेपी ने दो साल पहले बनाया दिल्ली विजय का प्लान

केजरीवाल से नाराज जाट-गुर्जरों को साधा, आरएसएस ने दिलाए झुग्गियों के वोट

बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिलीं।बीजेपी ने दिल्ली जीतने की प्लानिंग 2022 में एमसीडी चुनाव हारने के बाद ही शुरू कर दी थी। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार की जिम्मेदारी तक सारे फैसले गृह मंत्री अमित शाह ने किए। बीजेपी ने सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों से आए वोटर्स पर फोकस किया। वहीं 20 सीटों पर असर रखने वाले जाट और गुर्जरों को भी साधा।

जाट-गुर्जर वोटर्स को BJP ने साधा

दिल्ली में 360 गांव और 36 बिरादरी

जाट और गुर्जर वोटर 17-20%

22 से 25 सीटों पर दिखा असर

चुनाव में BJP कैंडिडेट

14%	11%
जाट	गुर्जर

चुनाव में AAP कैंडिडेट

11%	11%
जाट	गुर्जर

अमित शाह की स्ट्रैटजी और प्लानिंग का असर

सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुआई में सर्वे कराया। वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लीडरशिप ने उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां सौंपीं।दिसंबर में पहली मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली यूनिट ने कैंडिडेट की लिस्ट सामने रखी। अमित शाह ने इसे खारिज कर दिया। जनवरी में एक और बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी शामिल हुए। इसमें पार्टी के इंटरनल सर्वे को देखते हुए अमित शाह ने कैंडिडेट के नामों पर आखिरी फैसला लिया।चुनाव में बीजेपी को 2100 उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे थे। लिहाजा, पार्टी में कलह कम करने के लिए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करने में वक्त लिया गया।

एमसीडी चुनाव से सबक, प्रकोष्ठ और मोर्चा पर फोकस

पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील कश्यप के मुताबिक, एमसीडी चुनाव हारने के बाद ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। वे कहते हैं, 'एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 में से 104 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। इसके बाद से ही बीजेपी ने अपनी रणनीति और काम करने के तरीके में बदलाव किया।''पार्टी ने इस चुनाव में कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि प्रकोष्ठ और मोर्चा बनाए, ताकि वोट शेयर 40% के पार ले जा सकें। इसके वो कामयाब भी रहे। उन्होंने जाट, गुर्जर, त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित सभी तक पहुंच बनाई। 'बीजेपी ने चुनाव में जाति, रीजन और धार्मिक समूहों को टारगेट करने के लिए 27 प्रकोष्ठ या सेल और 7 मोर्चा बनाए। इनमें पूर्वांचल मोर्चा और मंदिर प्रकोष्ठ प्रमुख रहे। एमसीडी चुनाव से पहले सिर्फ 19 प्रकोष्ठ काम कर रहे थे। इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे जमीनी स्तर पर लोगों से बात करें और पार्टी की विचारधारा से जोड़ें।

दिल्ली में RSS के ये संगठन एक्टिव रहे

1. सेवा भारती	2. लघु उद्योग भारती	3. राष्ट्र सेविका समिति
4. भारतीय मजदूर संघ	5. विद्या भारती	6. भारत विकास परिषद

महाकुंभ की डुबकी से खुले सत्ता के द्वार
पेज-11

आरएसएस की मदद से दलित वोटर साथ आए

झुग्गियों के 15 लाख वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने झुग्गी-झोपड़ी अभियान शुरू किया। इसे दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने लीड किया। इसके तहत हर मंगलवार शाम 7 बजे बस्ती में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सालभर झुग्गी टूर्नामेंट करवाए। रक्षा बंधन, भाई दूज और अलग-अलग मौके पर ये प्रोग्राम कराए गए।झुग्गियों के वोट जोड़ने में आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई। आरएसएस में हमारे सोर्सेज के मुताबिक, चुनाव में आरएसएस की एंट्री 5 जनवरी से हुई। लोगों की सभाएं की गईं। उन्हें समझाया गया कि बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा।आरएसएस ने झुग्गी को टारगेट करने के लिए सेवा भारती, लघु उद्योग भारती, राष्ट्रीय सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती और भारत विकास परिषद को जमीन पर उतारा।

'आप' में टूट का फायदा उठाया

दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल गए। हालांकि करप्शन और शीशमहल जैसे मुद्दे उनके खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। लिहाजा, पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश की गई। केजरीवाल जब जेल में थे, तब उनकी गैरमौजूदगी में उपराज्यपाल को ध्वज फहराने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होता है। 'आप' चाहती थी कि ये जिम्मेदारी आतिशी को मिले। उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल को लेटर भी लिखा, लेकिन उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को चुना। कैलाश उस वक्त दिल्ली सरकार में गृह मंत्री और 'आप' सरकार के मुख्य जाट नेता थे।इसके बाद पार्टी में माहौल गहलोत के खिलाफ बना और उन्होंने 'आप' छोड़ दी। कैलाश ने अगले ही दिन बीजेपी जॉइन कर ली। वहीं, चुनाव से पहले 8 विधायकों और 20 से ज्यादा पार्टी वर्कर को 'आप' से तोड़कर बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई। लिहाजा, जमीन पर 'आप' के वर्कर कम होने लगे।सीनियर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता कहते हैं, आम आदमी पार्टी का संगठन इतना बड़ा नहीं है। उन्हें हरियाणा की हर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। कांग्रेस ने दिल्ली में 'आप' से बदला लिया है। कांग्रेस के हाथ से हरियाणा के तौर पर तो सिर्फ एक राज्य गया। 'आप' के हाथों से उनका गढ़ चला गया है। उनकी लीडरशिप केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक सब हार गए। इनके मार्जिन से ज्यादा कांग्रेस का वोट पड़े है।

प्रगतिशील राष्ट्रीय पाक्षिक
मालव समाचार
इंदौर
15 फरवरी 2025

नीतीश के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने में फेल हुए लालू

मुख्यमंत्री 'T' और 'R' टेंशन से दूर, तेजस्वी को तनाव

पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड कह रहे हैं। थका-चुका साबित कर वे बिहार संभालने में नीतीश को नाकाम बताने से तनिक भी परहेज नहीं करते। उनके पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नीतीश के लिए दरवाजा खोल कर बैठे हैं, पर तेजस्वी कह रहे कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'T' यानी टायर्ड और 'R' यानी रिटायर्ड से काफी दूर हैं। इससे विरोधियों को झटका लगा है।

नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव के तेवर पहले ऐसे नहीं थे। खासकर दूसरी बार नीतीश मंत्रिमंडल में आखिरी बार साथ रहने के बाद। नीतीश ने भले उनके प्रति तल्ख टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया। लालू की संतान को लेकर जब नीतीश ने यह कहा था कि इतने बच्चे कोई पैदा करता है, तब भी तेजस्वी के तेवर तल्ख नहीं हुए थे। पर, अब तो उनकी बोली इतनी टेढ़ी हो गई है कि नीतीश कुमार के समर्थक-शुभचिंतक तेजस्वी की खिल्ली उड़ाने लगे हैं। उनका कहना है कि साथ रहते उन्हें नीतीश टायर्ड या रिटायर्ड नहीं होते। जब नीतीश ने लालू यादव के ऑफर को नकार दिया तो अब तेजस्वी उनके लिए आरजेडी में दरवाजा बंद रहने की बात कहने लगे हैं।

लालू ने खोल रखा है दरवाजा

पखवाड़े भर पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और उसके बाद नए साल के पहले ही दिन ऐसे बयान दिए थे, जिससे बिहार की राजनीति में तूफान के संकेत मिलने लगे थे। भाई वीरेंद्र ने सियासी खेल का संकेत दिया था तो लालू यादव ने नीतीश की गलती माफ करते हुए उनके लिए आरजेडी का दरवाजा खोले रखने की बात कही थी। दोनों ने ये बात तब कही थीं, जब अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चा जोरों पर थी। नीतीश ने भी चुप्पी साध ली थी।

तेजस्वी को दरकार

नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले गोपालगंज और दूसरी बार मुजफ्फरपुर में नीतीश ने कहा कि एक-दो बार आरजेडी के साथ जाकर गलती कर दी थी। अब वैसी गलती नहीं करेंगे। जिस भाजपा ने उन्हें सीएम बनाया, उसका साथ अब वे नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार की सफाई आने तक तेजस्वी भी उनके प्रति तल्ख नहीं थे। अब तो उनके चेहरे और जुबान पर तिलमिलाहट साफ झलकने लगी है। वे कहते हैं कि नीतीश के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं।

नीतीश की चाल से सभी पस्त

बहरहाल, जो लोग नीतीश को बूढ़ा, बीमार और टायर्ड-रिटायर्ड बताते थकते नहीं, उन्हें भी उनके एक फैसले से एहसास हो गया होगा कि उनका आकलन-अनुमान कितना गलत है। हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के संदर्भ में। जेडीयू ने शेखपुरा के रहने वाले ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ललन जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता हैं। वे धानुक जाति से आते हैं, जिसका प्रभाव कमोबेश बिहार की सवा सौ विधानसभा सीटों पर माना जाता है। मोकामा समेत कई विधानसभा सीटों पर धानुक जाति के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। बिहार में धानुक जाति की आबादी 2.14 प्रतिशत है। राज्य में इनकी संख्या 27 लाख 96 हजार 605 है। नीतीश कुमार का ध्यान हर पॉकेट के वोट पर रहता है। यह कोई थका-हारा व्यक्ति थोड़े ही सोच सकता है।

जमीनी और सामान्य कार्यकर्ता को अवसर

कांग्रेस प्रवक्ता सुमन कुमार मल्लिक का कहना है कि ललन प्रसाद जैसे जमीनी और सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी पार्टी विशेष अवसर देती है तो पार्टी लाइन से अलग हट कर इस पर खुशी जाहिर करनी चाहिए। विधान परिषद के चुनाव में जेडीयू ने अपने समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता ललन प्रसाद को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। पूर्व में आरजेडी ने भी यूनुस लोहिया और मुन्नी रजक को विधान परिषद का सदस्य बनाया था, जो बेहद आम और जमीनी कार्यकर्ता थे। ललन प्रसाद समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ हैं।

लालू यादव ने किया एलान...

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे

विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे। इधर, उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बड़ा एलान करते हुए कहा कि हमलोग हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों इकट्ठा होकर इस देश में अपनी सरकार बनानी है। आपलोग कहीं किसी के सामने सिर नहीं झुकाना और ना हमने झुकाया है और न आपलोग किसी के सामने झुकना ।लालू प्रसाद ने कहा कि मैं आप लोगों ने अपील करता हूं कि आपलोग इस देश की रक्षा के लिए हम सब एक साथ खड़ा रहे। हम सरकार बनाएंगे। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे। जैसे झारखंड में डाला है और बिजली फ्री, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। हम जो बोलते हैं वह करते हैं। जो कहते हैं वह करना चाहिए।

बिहार चुनाव में इस बार फिर से 'बाहुबलियों' की ग्रैंड एंट्री के संकेत, 1990 वाला इतिहास खुद को दोहराएगा?

बिहार की राजनीति एक बार फिर 1990 के दौर में लौटने को बेताब है। सूबे में सक्रिय दोनों मजबूत सियासी गठबंधन- एनडीए और महागठबंधन की चुनावी तैयारियों से यही संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में जेडीयू के पास दो बाहुबली- आनंद मोहन और अनंत सिंह हैं, जो खुद या अपने परिजनों के लिए विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए का दूसरा घटक भाजपा भी सुनील पांडेय को बेटे को फिर उम्मीदवार बनाएगी, यह तय है। इसलिए कि उन्होंने उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। महागठबंधन में भी ऐसी ही तैयारी दिखती है। एलजेपी-आर ने भी सिवान में रईस खां और उनके भाई को अपने साथ लिया है तो यकीनन उनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करेगी। अपने समय में कुख्यात रहे दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी आरजेडी के साथ इसलिए आए हैं कि उन्हें पार्टी विधानसभा का टिकट देगी। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार बाहुबलियों की पदचाप जरूर सुनेगा। या तो वे खुद अपने लिए मैदान सजाते नजर आएंगे या अपने परिजनों के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू के बीच हाल में गोलीबारी की घटना यह बताती है कि चुनावी जंग इस बार कैसी रहेगी।

अनंत सिंह हों या उनकी पत्नी नीलम देवी हों, दोनों की जीत जितनी उनकी लोकप्रियता के कारण होती रही है, उससे कम भूमिका उनकी दबंगई की नहीं होती। पारस के साथ बाहुबली सूरजभान शिद्दत से खड़े रहे हैं। इस बार पारस उन्हें भी उम्मीदवार बनाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तो अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए पहले ही अपनी मां हिना शहाब के साथ आरजेडी की सदस्यता ले चुके हैं ।सिवान में आपराधिक छवि के रईस खान और उनके भाई की हाल ही एलजेपी-आर में एंट्री हुई है। हुलास पांडेय पहले से ही चिराग के साथ हैं। चिराग इनका भी इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में करेंगे ही। भाजपा और जेडीयू की तरह एलजेपी-आर भी इस बार बाहुबलियों पर दांव लगाने से पीछे नहीं रहना चाहती है ।भाजपा भले अलग अंदाज की पार्टी होने का दावा करे, पर बिहार में उसकी छवि भी दूसरे दलों से अलग नहीं। बाहुबली सुनील पांडेय अपने बेटे विशाल प्रशांत के लिए फिर जोर लगाएंगे ही। अब नीतीश को भी बाहुबलियों से परहेज नहीं है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद नीतीश उनके घर भी गए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने संकट में पाला बदल कर नीतीश का साथ दिया था। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी नीतीश कुमार ने ही प्रशस्त किया था। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी आड़े वक्त नीलम देवी की तरह ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश का साथ दिया था। इस बार तो जेडीयू में राजन तिवारी को भी टिकट देने की तैयारी है ।आरजेडी के स्तंभों में रहे भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन के रूठे परिवार को तेजस्वी ने अब मना लिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी की फिर से सदस्यता ले ली है। मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ चुकीं कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी भी असेंबली चुनाव में ताल ठोंकने को तैयार हैं।

जिलों के प्रभारी मंत्री पद को लेकर महायुति में मतभेद!

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें

मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़कर बंपर बहुमत हासिल किया है। हालांकि, कई अंदरूनी मुद्दों पर भाजपा, शिवसेना और राकांपा का यह गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता दिखा है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पद को लेकर उभरा तनाव हो या मंत्री पद के बंटवारे पर सामने आए मतभेद। तीनों ही दलों को इन मुद्दों पर आमने-सामने देखा गया। हालांकि, इन पार्टियों के नेतृत्व ने बाद में आपसी सामंजस्य से विवादों को दूर कर लिया। हालांकि, अब एक बार फिर महायुति में मतभेद सामने आया है। इस बार मसला है जिलों के प्रभारी मंत्री पदों के बंटवारे का।

ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्री, जिसे पालकमंत्री भी कहा जाता है, वह पद है क्या? इसे लेकर हालिया घटनाक्रम क्या हुआ? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं और खुद उन्होंने इसे लेकर क्या कहा है? इसके अलावा इस पद का इतिहास क्या रहा है?

क्या है महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री का पद?

भारत में हर राज्य में जब शासन के लिए सरकार का गठन होता है, तो एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता है। इसे कैबिनेट कहा जाता है और यही मंत्री परिषद राज्यों के सारे मामले देखता है। हालांकि, महाराष्ट्र में एक साधारण मंत्री परिषद के अलावा जिलों के प्रभारी मंत्रियों (जिन्हें प्रभारी मंत्री भी कहते हैं) की भी नियुक्ति की जाती है। यह प्रभारी मंत्री अलग-अलग जिलों के कामकाज की निगरानी के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनकी अपने जिलों के प्रति अलग से जिम्मेदारी तय होती है।यानी अगर किसी नेता को किसी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, तो उसकी यह जिम्मेदारी मंत्री परिषद में उसको दी गई जिम्मेदारी से अलग और अतिरिक्त होती है। महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों का पद कैबिनेट स्तर के बराबर का पद होता है और इनकी नियुक्ति भी सत्तासीन सरकार ही करती है।

क्या होता है प्रभारी मंत्रियों का काम, इनकी जरूरत क्यों?

गौरतलब है कि जिले में किसी प्रभारी मंत्री का काम, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारी और विधायक से अलग होता है। किसी जिले का प्रभारी मंत्री उस जिले में योजनाओं के लागू होने से लेकर अलग-अलग विभागों में समन्वय बनाने, जिले के विकास को सुनिश्चित करने का भी काम करता है। उन्हें जिले के प्रशासन की निगरानी और इसे निर्देशानुसार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक तरह से समझा जाए तो इस पद को बनाया ही इसलिए गया, ताकि किसी मंत्री को जिले के विकास के लिए भी जिम्मेदार बनाया जा सके।प्रभारी मंत्री जिले की योजना समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। यानी पालक मंत्रियों के पास जिलों में योजनाएं लागू कराने के लिए स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाने की भी जिम्मेदारी होती है। यह जिला योजना समिति (डीपीसी) पंचायतों और नगरपालिकाओं में आम हित के मामलों के लिए योजनाओं को बनाने का काम करती है। फिर चाहे वह पानी से जुड़ा मसला हो या सीवेज निपटान या क्षेत्र नियोजन का काम। प्रभारी मंत्री इन सब चीजों में निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है।

प्रभारी मंत्री अपने जिम्मेदारी वाले जिलों में बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, राजमार्गों-हवाई अड्डों, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्माण योजनाओं का भी हिस्सा होता है। वे जिले में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय निकायों के बजट की निगरानी भी कर सकते हैं। ये गार्डियन मिनिस्टर हर तीन महीने में बजट खर्च की समीक्षा करते हैं और केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। आपात स्थितियों में जिलों के प्रभारी मंत्री स्थानीय प्रशासन का नेतृत्व भी कर सकते हैं।महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्री का पद अपने आप में कितना जिम्मेदारी भरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुणे में इन मंत्रियों की अलग से भी जिम्मेदारियां तय हैं। यहां प्रभारी मंत्री अलंदी और देहू से पंढरपुर की सालाना तीर्थयात्रा में व्यवस्थाओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। वह गणेश चतुर्थी के आयोजन में तैयारियों की निगरानी का जिम्मा भी संभालता है।महाराष्ट्र में जिले के प्रभारी मंत्री का पद अधिकतर उन कैबिनेट मंत्रियों को ही सौंपा जाता है, जो उस जिले से ही चुनकर आए हों। हालांकि, कई बार ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री को उस जिले की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसके अलावा एक ही मंत्री कई जिलों का प्रभारी मंत्री हो सकता है।

नासिक जिले को लेकर तनाव क्यों?

दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बाद नासिक के प्रभार को लेकर भी राकांपा के माणिकराव कोकटे और शिंदे शिवसेना के दादा भुसे के बीच प्रतिद्वंद्विता देखी गई थी। कोकते ने इस जिले को राकांपा को देने की मांग के पीछे तर्क दिया था कि पार्टी के सात विधायक इसी जिले से आते हैं। दोनों पार्टियों में इस विवाद को देखते हुए सीएम फडणवीस ने जिले का प्रभार भाजपा की ओर से मंत्री गिरीश महाजन को दे दिया। इस फैसले से शिवसेना नाराज बताई गई है। राकांपा ने अब तक यह जिला हाथ से जाने पर बयान नहीं दिया है, लेकिन वह भी इस फैसले से नाखुश मानी जा रही है।

रायगढ़ जिले को लेकर विवाद की वजह क्या?

बता दें कि रायगढ़ और नासिक को लेकर महायुति में तनाव कोई नया नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब नई सरकार का गठन हुआ था, तब भी इन दोनों जिलों के प्रभारी मंत्रियों के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार राकांपा की अदिति तटकरे को ही प्रभारी मंत्री बनाने का मन बना चुकी थी। लेकिन शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले ने कहा था कि रायगढ़ से सरकार में तीन मंत्री हैं। इसलिए यह जिला शिवसेना को ही मिलना चाहिए।

शिंदे ने खुद अपनी नाराजगी की अटकलों को खारिज किया है

हालांकि, जब उनसे रायगढ़ और नासिक जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लेकर सवाल किया गया तो शिंदे ने कहा कि यह मामले सुलझा लिए जाएंगे। रायगढ़ जिले पर भरत गोगावले के बयान पर उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री की तरफ से दावा किए जाने में कुछ गलत नहीं है। गोगावले ने रायगढ़ में कई साल तक काम किया है। इसलिए उनकी मांग गलत नहीं है। हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से बात करुंगा।

गढ़चिरौली जिले को लेकर भी नाराजगी की खबरें

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के लिए खुद को प्रभारी मंत्री घोषित किया है, जबकि शिवसेना के आशीष जायसवाल को इसी जिले का संयुक्त प्रभारी मंत्री बनाया। बताया जाता है कि जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तत वह गढ़चिरौली का प्रभार चाहते थे, हालांकि उन्हें यह पद नहीं दिया गया था। ऐसे में इस जिले को लेकर भी महायुति में नाराजगी की बातें सामने आई हैं।

शिवसेना-राकांपा के दबाव में रोकी गई नियुक्तियां?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की साथी पार्टियों के बीच जिलों के बंटवारे को लेकर उठे तनाव के बाद रायगढ़ और नासिक में नियुक्तियों को टाल दिया था। सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं में यह बात सामने आई है कि फडणवीस ने यह कदम एकनाथ शिंदे के कहने पर उठाया।

महायुति की लाडली बहन अब 'इस' जिले की प्रभारी पंकजा मुंडे भी बीड से दूर, अदिति तटकरे ने बरकरार रखी रायगढ़ सीट

पूरे महाराष्ट्र की नजर इस बात पर थी कि राज्य के 36 जिलों का पालकमंत्री यानी प्रभारी मंत्री कौन होगा? । इसमें मंत्री पद के आवंटन के अनुसार चार लाडली बहनों को जगह दी गई है। पंकजा मुंडे, अदिति तटकरे, माधुरी मिसाल और मेघना बोर्डिकर को प्रभारी मंत्री का पद सौंपा गया। पंकजा मुंडे को जालना के प्रभारी मंत्री का पद सौंपा गया है। वहीं अदिति तटकरे एक बार फिर रायगढ़ की पालकमंत्री का पद संभालेंगी। माधुरी मिसाल कोल्हापुर की सह-प्रभारी मंत्री के रूप में काम करेंगी। मेघना बोर्डिकर को परभणी के प्रभारी मंत्री का पद सौंपा गया।दरअसल पंकजा मुंडे पर्यावरण मंत्री हैं और उन पर जालना जिले की जिम्मेदार होंगी। लेकिन संतोष देशमुख हत्या मामले में धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें बीड के पालकमंत्री पद से हटा दिया गया है। इसमें पंकजा मुंडे को बीड के प्रभारी मंत्री पद से भी दूर रखा गया है। मुंडे भाई-बहनों को बीड के प्रभार से वंचित करना चर्चा का विषय बन गया है।यह भी देखा गया कि रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद को लेकर अदिति तटकरे और भरत गोगावले के बीच रस्साकशी चल रही थी। भरत गोगावले ने पहले भी कई बार प्रभारी मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी। मंत्रिमंडल में उनके पास रोजगार गारंटी विभाग है और चर्चा थी कि उन्हें रायगढ़ के प्रभारी मंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन रायगढ़ के प्रभारी मंत्री का पद फिर से अदिति तटकरे को सौंप दिया गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिले की राजनीति क्या करवट लेती है।

पीएम मोदी के तीर्थ दर्शनों में छिपा है कमल खिलाने का राज!

संगम स्नान से निकला राजनीतिक संदेश....
क्या बिखरे हिंदू वोटों को एक कर पाएगी बीजेपी?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। माघ की अष्टमी के शुभ अवसर पर पीएम मोदी के संगम में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस 'मुहूर्त' में संगम में डुबकी लगाई, उसी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मतदान का भी 'मुहूर्त' था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी के इस डुबकी से राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे वो हिंदू वोट फिर उसके पास वापस आएगा, जो पिछले दिनों उससे छिटक गया था और ऐसा हुआ भी।

देश में इन दिनों जातिगत सर्वेक्षण और जाति जनगणना की राजनीति का जोर है। विपक्ष की अधिकांश पार्टियां इसके समर्थन में हैं। कभी यह सामाजिक बदलाव और न्याय की राजनीति करने वाले दलों का प्रमुख एजेंडा हुआ करता था। लेकिन पिछले एक-दो साल से इसको लेकर कांग्रेस मुखर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने हर राजनीतिक कार्यक्रम में इसकी बात करते हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार जाति जनगणना कराएगी। यहां तक कि उनकी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जाति सर्वेक्षण कराए भी हैं। इन सरकारों का दावा है कि वो इसके आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रहे हैं।

पीएम मोदी के स्नान के मायने

पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाकर उन आलोचनाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की है, जो वहां 29 जनवरी को मची भगदड़ के बाद की जा रही है। यह एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर भी मुहर है, जो भगदड़ के बाद से विपक्ष के निशाने पर है।पीएम मोदी 2019 के कुंभ मेले में भी गंगा स्नान किया था। उन्होंने गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पैर भी धोकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। पीएम मोदी का समरसता का यह संदेश जनता तक पहुंचा भी था।

महाकुंभ की डुबकी से खुलें दिल्ली सत्ता के द्वार?

दिल्ली में भाजपा एकमात्र बार 1993 में सत्ता में आई थी, उसके बाद 1998 में कुर्सी कांग्रेस के हाथ चली गई थी। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी 27 सालों से भाजपा विधानसभा में निर्णायक जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में पार्टी संभावनाएं देख रही थी। विकास के साथ हिंदुत्व की जुगलबंदी भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। इस बार भी यह प्रयोग आजमाया जाता दिख रहा है। यूं तो महाकुंभ में पूरे देश-दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन यूपी-बिहार के लोगों की बहुतायत होती है। दिल्ली में 20% से अधिक वोटर पूर्वांचल के है, जिनका करीब 30 सीटों पर असर है। ऐसे में मतदान के दिन आस्था की 'डुबकी' से अपेक्षाओं की चमक बढ़ाने पर भी नजर रही। आस्था और राजनीति का यह संयोग पहले भी घटता रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद मोदी केदारनाथ में ध्यान लगाने चले गए थे। अगले दिन वह बद्रीनाथ में दर्शन कर रहे थे और देश में आखिरी चरण का मतदान चल रहा था। इस बार भी आखिरी चरण के चुनाव के दिन जब पीएम कन्याकुमारी में आध्यात्मिक शांति पाने की प्रक्रिया में जुटे थे, मतदाता आखिरी चरण के मतदान के जरिए देश का सियासी भविष्य तय करने में जुटे थे। हालांकि, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पीएम का दौरा फरवरी के पहले सप्ताह में इसलिए तय हुआ है, क्योंकि 3 फरवरी तक महाकुंभ में प्रमुख स्नान हैं। उनके पहले आने से सुरक्षा-व्यवस्था और प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा होती, इसलिए पीएम ने प्रमुख स्नान व आयोजनों के बाद महाकुंभ में आने का निर्णय लिया है।

क्या जाति जनगणना से बीजेपी को नुकसान होगा

जाति जनगणना को लेकर जारी लड़ाई को बीजेपी अपने वोटों के बिखराव के रूप में देख रही है। हालांकि वो इसका न तो खुल कर विरोध कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन। वह ऊहापोह की स्थिति में है। दरअसल जाति जनगणना की स्थिति में यह पता चल जाएगा कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है और देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। बीजेपी को डर है कि इससे उसके हिंदुत्व वाले वोटों में बिखराव होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में उसकी पैठ कमजोर हो जाएगी। माना जाता है कि ओबीसी ही देश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसलिए बीजेपी नेताओं का जोर अब हिंदुत्व की बजाय सनातन की राजनीति पर है। वो सनातन के डोर में सबको बांधना चाहते हैं।उनको लगता है कि सनातन की डोर हिंदुत्व से भी मजबूत है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन धर्म की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ को 'एकता का महाकुंभ' बता चुके हैं।

बीजेपी नेताओं ने पकड़ी संगम की राह

बीजेपी और उसके नेता महाकुंभ में स्नान पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई थी और संगम के तट से कई विकास योजनाओं का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसलिए ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों को प्रयागराज महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। वो लोग प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं।पीएम मोदी से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री संगम में स्नान कर चुके हैं।

वोटिंग और पीएम नरेंद्र मोदी

लोकसभा चुनाव

- **07 मई 2024**
  लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ. पीएम मोदी ने पांच मई को अयोध्या के राम मंदिर में पूजा कर रोड शो किया.
- **10 मई 2023**
  कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. पीएम मोदी ने राजस्थान के उदयपुर के श्रीनाथजी मंदिर पूजा-पाठ किया.
- **13 मई 2024**
  लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान. पीएम मोदी ने बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में सेवा की.
- **20 मई 2024**
  लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग हुई. पीएम मोदी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.
- **19 मई 2019**
  लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग हुई. पीएम मोदी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की.

वोटिंग और पीएम नरेंद्र मोदी

विधानसभा चुनाव

- **05 अक्टूबर 2024**
  हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान हुआ. पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के जगदंबा माता मंदिर में पूजा-अर्चना की.
- **27 मार्च 2021**
  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान. पीएम मोदी ने बांग्लादेश के ढाका में यशोश्वरी मंदिर शक्ति पीठ में पूजा-पाठ किया. ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर भी गए.
- **12 दिसंबर 2017**
  गुजरात विधानसभा का चुनाव दो चरण में हुआ. अंतिम चरण का मतदान 14 दिसंबर को हुआ. पीएम मोदी ने 12 दिसंबर को मेहसाणा के अंबाजी मंदिर में पूजा-पाठ किया.
- **08 मार्च 2017**
  यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान. पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा-पाठ किया.

मध्यप्रदेश शासन

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

देश का दिल
लिख रहा
**विकास का
नया अध्याय**

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएँ

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

24 25 फरवरी 2025, भोपाल

समिट की रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से शुभारंभ

- सेक्टोरल समिट
- थीमेटिक सेमिनार
- एग्जीबिशन एंड एक्सपो
- प्रवासी मध्यप्रदेश

पंजीकरण करने के लिए स्कैन करें।
www.investmp.in

D-19293/24

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विनोद खुजनेरी द्वारा अपना देश प्रिंटर्स से अनुबंध पर 204 शेखर एवेन्यू, सांघी कॉलोनी, इंदौर 452001 से मुद्रित तथा प्रकाशित।
संपादक: विनोद खुजनेरी। मोबाइल: 98270-10709। आरएनआई पंजीयन क्रमांक 13186/67